

श्री अशोक चौधरी
वकील
जोधपुर

वर्षीय सम्मेलन तलब किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय द्वारा वार्ड रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीवगण को किया जाकर विभाजन की डिक्री सादर की गई। अधीनस्थ कुसलिव विवादवस्तु भूमि का विभाजन माप सीमा के आधार पर तथा वादीवगण को वादवस्तु भूमि से बेखजल करना चाहते हैं। विभाजन करवाये बिना मकान निर्माण कार्य करवाना चाहते हैं वगैरह का 1/4 हिस्सा है। प्रतिवादीवगण विवादवस्तु आराजी का संख्या तीन से सात का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या आठ से हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या एक व दो का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी बीघा 08 बिस्वा भूमि ग्राम भीपलगाह एम.बी. से वादीवगण का 1/4 बिस्वा, खसरा नं. 2924 रकबा 4 बीघा 09 बिस्वा कुल रकबा 06 किया गया कि विवादवस्तु भूमि खसरा नं. 2923 रकबा 1 बीघा 19 एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट इस आधार का पेश संक्षेप से प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रैस्पी. द्वारा है।



की धारा 223 के तहत दिनांक 08 अगस्त 2019 को पेश की गयी अदालत द्वारा के समक्ष राजस्थान कायदाकारी अधिनियम, 1955 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम 1955 के खिलाफ आगोच्य अधीन व अन्य बगाम जागराम इत्यादि अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 एवं डिक्री दिनांक 28 जून 2019 राजस्व वाद संख्या 03/2019 बादाय सहाराक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भीपलगाह निर्णय दिनांक : 20 अक्टूबर, 2021

निर्णय

श्री अशोक चौधरी, अधिवक्ता, रैस्पी.-संख्या एक से धारा 5 श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रैस्पी. संख्या 5

राज्य अल्पसंख्यक आयोग
राज्य अल्पसंख्यक आयोग

आधार पर विधिसम्मत एवं व्यापक संवाद निर्णय पारित किया गया
अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्ष की समर्पित सलाहों के
वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार कारतदार घोषित किया है।
पक्षावली पर उपलब्ध अभिलेख एवं नमावदी के अनुसार ही
पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा
न्यायालय द्वारा उभय पक्ष के अधिवक्तागण की सहमति के आधार
के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ
नवाब में रेपॉर्ट्स के अधिवक्ता ने अभीगट के अधिवक्ता
को अपारत फरमाया जावे।
पारित अभीगटगण प्रथमिक डिप्टी एवं निर्णय दिनांक 28 जून 2019
अभीगट स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा
आवे में अभीगट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अभीगट
आने वाले बेदानकाल रामसुख के हिस्से का ही बेदान हुआ है।
में जिस पड़ोस के बीच की भूमि बेची गयी है, तब उसके बीच में
पहले से वला आ रहा है, जिसको वादीगण के खरीद के दरवाजे
भूमि का पुरवा बंटवाडा भौके पर वादीगण ने अपने खरीद से भी
बाड व तारबंदी, कच्चे पत्थरों की दीवार बनी हुई है। इस प्रकार
किया है। वादीगण के कच्चासुदा भूमि के चारों तरफ कांठों की
बंटवाडा नहीं होने का झूठा कथन करते हुए वर्तमान वाद परचल
वादीगण को कच्चा सुदूँ किया है। वादीगण ने वादखस्त भूमि का
आ रहे है, उक्त बेदानकालों में भूमि के पड़ोस अतिक्रम करके
उक्त रामसुख के हिस्से की भूमि पर कानिज है एवं कारत करते
लियाकर भौके पर वादीगण का कच्चा करवाया, तब से वादीगण
ने अपने बेदानकालों में भी उक्त बंटवाडा भौके पर होने की बात



निदेशक
राजस्थान न्यायिक प्रणाली
जोधपुर

निरास कोर्ट इत्यादी पक्षिका जाला उचित नही है।
अदालत जाला की राय में समर्थन किये जाने योग्य पायी जाती है,
पूर्ण अवसर प्राप्त है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थान निर्णय एवं डिक्ली
के समक्ष उपस्थित होकर विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज करवाने का
डिक्ली पारित किया जाना शेष है। अधीनस्थान के पास अधीनस्थ न्यायालय
उच्च/उपस्थान है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अशी तक अंतिम निर्णय एवं
किया जाना पाया जाता है। जहां तक बटवाड़ा प्रस्ताव पर अधीनस्थान की
की नमावंदी संवाद: 2059-62 में दर्ज हिस्से अगुसार ही खातेदार धारित
प्राथमिक डिक्ली दिनांक 28 जून 2019 के त्रिंसे वादीवण एवं प्रतिवादीवण
से वारड का 1/4 हिस्सा दर्ज है। अधीनस्थान न्यायालय द्वारा निर्णय एवं
प्रतिवादी संख्या तीन से सात का 1/4 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या आठ
वादीवण का 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या एक व दो का 1/4 हिस्सा,
4 बीघा 09 बिस्वा कुल रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा किस्म चाही द्वितीय में
आराजी खसरा नं. 2923 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 2924 रकबा
खाता संख्या 173 पुराना खाता संख्या 163 के भूगोलीक विवादखसरा
नमावंदी संवाद: 2059-2062 ग्राम भोपागवाड एम.बी. तहसील भोपागवाड के
आधीनस्थान अख्यतन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थान
नमावंदीवणक मगन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थान का
उभयपक्षकारन के अधीनस्थान की उपस्थान बहस पर
निवेदन किया।
परिस्थितियों के अगुश्य विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का
विज्ञान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं
की जाते।

है। अतः अधीनस्थान द्वारा पारित अधीनस्थान सारहीन होने से खारिज



उपरोक्त विद्वान एवं विशेषज्ञ के आचार पर अधीन अधीन खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर अधीनस्थ निरीक्षक एवं डिप्टी कमिश्नर द्वारा 28 जून 2019 राजस्व वाद संख्या 03/2019 वाद व अधीनस्थ न्यायालय इत्यादि को यथावत रखा जावे। तदनुसार डिप्टी

पदा जारी है।

निरीक्षक एवं सहायक न्यायालय में सुनवाई अथवा

2019/03/28

राजस्व अधीनस्थ निरीक्षक, गोरखपुर

राज्य अर्थ मंत्रालय
वायपूर

अपील अन्वयेत धारा 223 राजस्थान कायदाकरी अधिनियम 1955
व्यक्तिगत आदेश सहायक कलेक्टर श्रीपालवाड विभाग एव
डिप्टी कमिश्नर 28 जून 2019 राजस्व वाद संख्या 03/2019 वाद

व अ न्य बलात् जालाम इत्यादि

डिप्टी कमिश्नर अपील
अन अदालत राजस्व अपील याचिकाची, वायपूर
इंजलस श्री नरनादन वाड्ड, आर.ए.एस.

1. वाद पुन श्री वेरसाम
2. सुण्डराम पुन श्री हेमराम
3. वेनराम पुन श्री अलराम
4. धाराम पुन श्री गुलजाम श्री वातियाळ, श्रीपालवाड, तहसील श्रीपालवाड, जिगा वायपूर।
5. राजस्थान सरकार वरिचे तहसीलदार श्रीपालवाड।

व
न
म

01. जालराम पुन श्री शिवराम
02. धाराम पुन श्री शिवराम
03. रामनिवास पुन श्री शिवराम
04. रामनारायण पुन श्री अदराल
05. कानराम पुन श्री अदराल
06. रामराव पुन श्री अदराल
07. शांत पत्नी श्री अदराल
08. वेनराम पुन श्री अदराल
09. वाड्डाळ पुन श्री जालराम
10. अर्जुनराम पुन श्री जालराम
11. वीरु श्री जालराम

अपीलवाड



